संकल्प
पत्र-2024
महाराष्ट्र विधानसभा
चुनाव
भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र

विकसित महाराष्ट्र, विकसित भारत के संकल्प का सबसे अहम हिस्सा है

- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी

मा. श्री चंद्रशेखर बावनकुळे
प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र

जय भवानी, जय शिवाजी!

भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में नए बदलाव लाने में अग्रणी भूमिका निभाई है और राज्य को देश के प्रमुख राज्यों में से एक बनाने की दिशा में काम किया है। महायुति सरकार ने राज्य की प्रगति को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। 2.5 साल के शासनकाल में हमने राज्य की प्रगति और समृद्धि के एक नए युग की नींव रखी है, जो राज्य के हर नागरिक की आकांक्षाओं और सपनों से प्रेरित है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार ने भारत को असाधारण विकास और अवसरों वाला देश बनाया है। यहां महाराष्ट्र में हमारी सरकार ने इसी भावना को अपनाया है, साहसी सुधारों और समावेशी नीतियों को लागू करते हुए राज्य को आगे बढ़ाया है। हमारी उपलब्धियां, चाहे वह बुनियादी ढांचे, कृषि, स्वास्थ्य या शिक्षा के क्षेत्र में हों, यह दर्शाती हैं कि हम एक "जन-प्रथम" शासन मॉडल के प्रति प्रतिबद्ध हैं, जो विकास को राज्य के हर कोने और समुदाय तक पहुँचाने का उद्देश्य रखता है।

महाराष्ट्र की संस्कृतिक विरासत और अस्मिता हमेशा हमारी प्राथमिकता रही है। हमने विभिन्न पहलों के माध्यम से इस अस्मिता का सम्मान किया है: नौसेना के ध्वज पर छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रतीक चिह्न, मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देना, और लंदन में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के घर का अधिग्रहण करना। लेकिन आज, कुछ ताकतें राज्य की प्रगति को रोकने के लिए गलत धारणाएँ और भ्रांतियां फैलाने का प्रयास कर रही हैं।

हम "एक महाराष्ट्र, श्रेष्ठ महाराष्ट्र" की विचारधारा में विश्वास रखते हैं और युति - गती - प्रगति के आदर्श को समर्पित हैं। पिछले कुछ वर्षों में, हमने अपने वादों को साकार करने के लिए लगातार कार्य किया है। बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर सृजित करने से लेकर, स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र में क्रांति लाने तक, हमने एक मजबूत और समृद्ध राज्य की नींव रखी है।

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 'लाड़की बहिन योजना' शुरू की गई है, जिसमें उन्हें प्रति माह ₹1,500 की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। यह योजना, जो स्व. मनोहर परिकर द्वारा गोवा में प्रारंभ की गई थी, भाजपा शासित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सफल रही है। महाविकास आघाडी ने ऐसी योजनाओं की आलोचना की है, लेकिन हम इस योजना को महाराष्ट्र में जारी रखने का संकल्प लेते हैं। हम राज्य को सूखा मुक्त बनाने के लिए किसानों के पंप सेटों के बिजली बिलों की माफी और मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, साथ ही नीलवांडे, तेम्बू लिफ्ट सिंचाई, जलयुक्त शिवर, नार-पार और डमन गंगा-गोदावरी जैसी परियोजनाओं का भी समावेश किया गया है।

भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो अपने घोषणापत्र को गंभीरता से लेती है, अपने वादों को पूरा करती है और हर साल गहन समीक्षा करती है। यह घोषणापत्र महाराष्ट्र को सबसे उन्नत और समृद्ध राज्य बनाने के हमारे संकल्प का प्रतीक है, और इसे एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था में बदलने का हमारा उद्देश्य है। हमारा लक्ष्य राज्य को सूखा मुक्त बनाना, रोजगार के अवसर सृजित करना, विश्व-स्तरीय बुनियादी ढांचा विकसित करना, और प्रत्येक परिवार को आवास और स्वच्छ जल प्रदान करना है। आइए एक समृद्ध, आत्मनिर्भर और सशक्त महाराष्ट्र का निर्माण करें, जहां प्रत्येक नागरिक आगे बढ़ेगा और हर सपना साकार होगा।

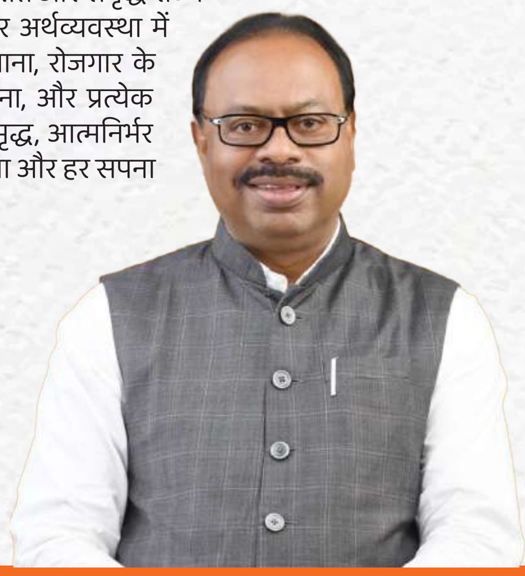

धन्यवाद, जय महाराष्ट्र

चंद्रशेखर बावनकुळे

राज्य अध्यक्ष, भाजपा, महाराष्ट्र

मा. श्री देवेंद्र फडणवीस
उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र

मनोगत...

प्रिय बहनों और भाइयों,

॥ जय भवानी, जय शिवाजी ॥

भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र को प्रगति और समृद्धि की ओर ले जाने की जिम्मेदारी स्वीकार की है। "एक महाराष्ट्र - श्रेष्ठ महाराष्ट्र" के दृष्टिकोण से, भाजपा ने हमेशा विकास, प्रगति और जनकल्याण को प्राथमिकता दी है, महाराष्ट्र धर्म को संजोया और आगे बढ़ाया है। 'महायुती - गती - प्रगती' के संकल्पना से, हमने महाराष्ट्र की प्रगति के लिए सर्वोत्तम विचारकों और प्रयासों को एकत्रित किया है। हमें दृढ़ विश्वास है कि हम सब मिलकर महाराष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं।

मा. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय गृह मंत्री मा. अमित भाई शाह जी के मार्गदर्शन और सहयोग से महाराष्ट्र ने मविआ के अढ़ाई साल के शासनकाल का अंधेरा छोड़कर 2014 से अब तक उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। निवेश, रोजगार और आधारभूत संरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में हमारा राज्य देश में शीर्ष स्थान पर पहुंचा है।

महिलाओं का सशक्तिकरण हमारे दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण घटक है, और "लाडकी बहिन योजना" के तहत हम अपनी बहनों को आर्थिक स्वावलंबन के लिए मासिक 1,500 रुपये की सम्मान निधि प्रदान कर रहे हैं। इसी तरह, किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता भी दृढ़ है; महायुती सरकार ने किसानों को मुफ्त बिजली दी है, जिससे अब उन्हें शून्य राशि के बिल मिल रहे हैं। हम जलयुक्त शिवार योजना को पुनः प्रारंभ कर और नदी जोड़ परियोजनाओं की योजना बनाकर महाराष्ट्र को सूखा मुक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इन प्रयासों के माध्यम से, विभिन्न क्षेत्रों में वैश्विक निवेश आकर्षित कर हमारा राज्य आर्थिक महाशक्ति की ओर अग्रसर हो रहा है, जिसमें सेमीकंडक्टर और हरित ऊर्जा परियोजनाएं भी शामिल हैं। इसलिए, देश में आने वाले कुल निवेश का 52 प्रतिशत हम राज्य में लाने में सफल रहे हैं।

राज्य की एक मजबूत नींव रखी गई है, और हमें पूरा विश्वास है कि यह ठोस नींव सभी नागरिकों के लिए समृद्ध फल देने वाला वृक्ष बनेगी। यदि हम यह गति बनाए रखते हैं, तो ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में महाराष्ट्र की सफलता अनिवार्य होगी। हम समृद्धि और अवसरों के दृष्टिकोण से देश का अग्रणी राज्य बनेंगे।

यह चुनाव केवल सरकार चुनने के लिए नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के विकास, विरासत और आकांक्षाओं को संजोने के लिए है। जनता की क्षमताओं पर विश्वास रखने वाली सरकार को चुनना अत्यावश्यक है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में बाहर निकलें, मतदान करें, और भाजपा एवं महायुति सरकार के साथ एक मजबूत, अधिक समृद्ध महाराष्ट्र की यात्रा का समर्थन करें। "एक महाराष्ट्र - श्रेष्ठ महाराष्ट्र" के इस वचन को हकीकत में बदलें।

धन्यवाद, जय महाराष्ट्र!

देवेंद्र फडणवीस

उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

मा. श्री सुधीर मुनगंटीवार

अध्यक्ष, जाहीरनामा समिती

वंदे मातरम्!

यह वर्ष हम महाराष्ट्र के आराध्य देवता छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का 350वां वर्ष, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर की जयंती का 300वां वर्ष, वीर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती का 150वां वर्ष, संविधान का अमृत महोत्सव, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का 150वां वर्ष और हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के रूप में मना रहे हैं। इन सभी से प्रेरणा लेते हुए, भाजपा-महायुती के माध्यम से महाराष्ट्र के विकास की गति को और आगे बढ़ाना हमारा लक्ष्य है। इसलिए विधानसभा चुनाव 2024 को विशेष महत्व प्राप्त हुआ है।

2019 के विधानसभा चुनावों के बाद, महाराष्ट्र ने विकास में एक ठहराव का दौर देखा। लेकिन उस कठिन समय को समाप्त कर, हमने प्रगति के एक नए युग की नींव रखी है। 2019 से 2022 तक के उस काले दौर की पुनरावृत्ति हमें अब नहीं होने देनी है। इसलिए सतर्क रहते हुए, हमें इस चुनाव में कठोर परिश्रम करना है। इसलिए, पूरी सतर्कता और समर्पण के साथ, हमें इस चुनाव में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना है।

हाल ही में केंद्र में भाजपा और सहयोगी दलों की सरकार बनी है। 2014 से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने हर क्षेत्र में प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुआ है। इसी प्रकार, माननीय श्री अमित भाई शाह जी, माननीय श्री जे.पी. नड्डा जी जैसे वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी देश में जोश के साथ आगे बढ़ रही है। महाराष्ट्र के विकास और प्रगति को केंद्र सरकार के सहयोग से आगे बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र में भाजपा-महायुति सरकार का आना आवश्यक है और हमें विश्वास है कि महायुति की सरकार फिर से आएगी।

चुनाव में उतरते हुए, राज्य के विकास के लिए हमारी नीति क्या होगी, किन मुद्दों पर हम जोर देंगे, इसे मतदाताओं के सामने रखने के लिए एक घोषणापत्र तैयार किया गया है। इसके लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों का चयन कर, हर क्षेत्र में विशेषज्ञों की उप-समितियां गठित की गयी। समाज के विभिन्न विशेषज्ञों और आम जनता को भी राज्य के विकास में अपने विचार और सुझाव देने का आह्वान किया गया था। इसके लिए एक समर्पित ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर बनाए गए थे। इस पहल को जनता से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली।

उपरोक्त सभी माध्यमों से प्राप्त सुझावों और अभिप्रायों पर गहन विचार-विमर्श कर महाराष्ट्र के विकास का सर्वसमावेशी घोषणापत्र तैयार करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

यह घोषणापत्र महाराष्ट्र को ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने का मार्ग दिखाता है। इसमें कृषि क्षेत्र को प्रतिष्ठा, सुरक्षा और समृद्धि प्रदान करने और महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और अवसरों की समानता सुनिश्चित करने का उद्देश्य है। विकास का फल अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की अंत्योदय की अवधारणा को हम इस घोषणापत्र के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। किसान, युवा, महिलाएं, मजदूर और वरिष्ठ नागरिकों जैसे समाज के सभी वर्गों को शामिल करते हुए यथासंभव सभी का घोषणापत्र में समावेश किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की राज्य के हित और विकास के प्रति ईमानदार भूमिका को इस घोषणापत्र के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

घोषणापत्र समिति के माध्यम से पार्टी ने मुझे सेवा का अवसर दिया और मुझ पर भरोसा किया, इसके लिए मैं पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही, इस घोषणापत्र को तैयार करने में सभी विषय समितियों के अध्यक्ष, सदस्य और उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया।

आप सभी से अनुरोध है कि इस घोषणापत्र का अध्ययन करें, इसमें किए गए वादों को समझें और इसे प्रभावी ढंग से मतदाताओं तक पहुँचाएं।

जय हिंद, जय महाराष्ट्र!

सुधीर मुनगंटीवार
अध्यक्ष, घोषणापत्र समिति

मुख्य जाहीरनामा समिती

समिती सदस्य

अध्यक्ष - मा. श्री सुधीर मुनगंटीवार

डॉ. विनय सहस्रबुद्धे	श्री दिलीप कांबळे
श्री माधवराव भंडारी	श्री पाशा पटेल
ॲड. उज्ज्वल निकम	श्री अनिल सोले
डॉ. भारतीताई पवार	विधायक श्री पराग आळवणी
विधायक श्री मंगल प्रभात लोढा	श्री लक्ष्मण सावजी
विधायक श्री सुभाष देशमुख	श्री सुरेश हावरे
विधायक श्री संभाजी निलंगेकर	श्री विश्वास पाठक
सांसद श्री धनंजय महाडिक	श्री केशव उपाध्ये
सांसद सौ. स्मिता वाघ	सौ. माधवी नाईक
विधायक श्री अतुल भातखळकर	श्री राजेश पांडे
श्री नरेंद्र पवार	श्री योगेश गोगावले
श्री मिलिंद तुळसकर	सौ. नीता केळकर
श्री अमोल जाधव	श्री किरण पातुरकर
आचार्य तुषार भोसले	श्री दयाशंकर तिवारी

विषय सूची

01	25 प्रमुख मुद्दे	10
02	कृषि एवं सम्बंधित क्षेत्र	16
03	अर्थव्यवस्था और उद्योग	22
04	शिक्षा	26
05	युवा और खेल	28
06	स्वास्थ्य	32
07	महिला सम्मान	36
08	सामाजिक न्याय	38
09	प्रशासन और व्यवस्था	42
10	आधारभूत संरचना	44
11	शहरी विकास	46
12	ग्रामीण विकास	48
13	संस्कृति और पर्यटन	50
14	वन, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन	54
15	मुंबई महानगर क्षेत्र	56

25 प्रमुख मुद्दे

हम **लाड़की बहिन योजना** के अंतर्गत प्रति महिला को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को **₹1,500 से ₹2,100 तक बढ़ाएंगे** इसके अलावा, उनकी वित्तीय स्वतंत्रता को मजबूत करने हेतु वित्तीय साक्षरता का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा, और पूरे महाराष्ट्र में **25,000** महिलाओं को **पुलिस बल में भर्ती** करेंगे।

किसानों की ऋण माफी और किसान सम्मान योजना के अंतर्गत **वार्षिक राशि ₹12,000 से बढ़ाकर ₹15,000** की जाएगी, साथ ही **न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के समन्वय में 20% तक भावांतर** योजना लागू की जाएगी।

हम राज्य के सभी गरीबों को **खाद्य सुरक्षा और आवास** प्रदान करेंगे।

हम **वृद्धावस्था पेंशन** को **प्रति माह ₹1,500 से ₹2,100 तक बढ़ाएंगे**, जिससे पूरे महाराष्ट्र में वरिष्ठ नागरिकों को अधिक आर्थिक सुरक्षा और सम्मान मिलेगा।

हम **आवश्यक वस्तुओं की कीमतें स्थिर करेंगे** ताकि पूरे महाराष्ट्र में परिवारों को बाजार के उतार-चढ़ाव से सुरक्षित किया जा सके।

25 प्रमुख मुद्दे

हम पूरे महाराष्ट्र में **10 लाख छात्रों** को उनकी शिक्षा समर्थन के लिए और परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए **₹10,000 का मासिक मानदेय** प्रदान करेंगे। साथ ही राज्य में **25 लाख रोज़गार के अवसर** उपलब्ध कराएंगे।

राज्य के 45,000 गांवों में **पांधण रास्ते बनाए जाएंगे।**

हम **आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा सेवकों** की आर्थिक सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें **₹15,000 का मासिक मानदेय** और बीमा कवरेज देंगे।

वीज बिलात ३०% कपात करके सौर और अक्षय ऊर्जेवर ऊर्जा पर भर दिया जाएगा।

सरकार बनने के बाद, पहले 100 दिनों के भीतर, हम **'विज़न महाराष्ट्र 2029'** प्रस्तुत करेंगे।

25 प्रमुख मुद्दे

2028 तक महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है।

महाराष्ट्र को प्रौद्योगिकी, उत्पादन और नवीन विचारों के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे:

a. **'मेक इन महाराष्ट्र' नीति** के कार्यान्वयन से महाराष्ट्र को भारत के प्रमुख उत्पादन राज्य के रूप में मज़बूती से स्थित और सशक्त किया जाएगा।

b. महाराष्ट्र को **फिनटेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की वैश्विक राजधानी** के रूप में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए वैश्विक फिनटेक कंपनियों को आकर्षित करने वाला अनुकूल वातावरण बनाया जाएगा और आर्थिक प्रौद्योगिकी में नई संकल्पनाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके साथ ही AI अनुसंधान, नवाचार और विकास को बढ़ावा देने के लिए देश का पहला समर्पित **AI विश्वविद्यालय** की स्थापना की जाएगी।

c. नागपुर, पुणे, छत्रपति संभाजीनगर, अहिल्यानगर और नासिक को **आधुनिक एयरोनॉटिकल और स्पेस उत्पादन केंद्र** बनाकर एक उन्नत एयरोस्पेस प्रौद्योगिकी और उत्पादन हब के रूप में विकसित किया जाएगा।

किसानों की आय बढ़ाने के लिए हम निम्नलिखित व्यापक पहल लागू करेंगे:

a. किसानों को खरीदे गए उर्वरकों पर चुकाए गए **सम्पूर्ण राज्य माल एवं सेवा कर (एसजीएसटी) पर छूट मिलेगी,** जो उन्हें सब्सिडी के रूप में वापस कर दी जाएगी।

b. यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को **सोयाबीन के लिए प्रति क्विंटल ₹6,000 का न्यूनतम मूल्य मिले,** हम सोयाबीन उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के लिए एक समर्पित मूल्य श्रृंखला स्थापित करेंगे।

25 प्रमुख मुद्दे

वर्ष 2027 तक महाराष्ट्र में **50 लाख 'लखपति दीदियों'** का सृजन किया जाएगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर **500 स्वयं सहायता समूहों के लिए एक औद्योगिक क्लस्टर स्थापित** किया जाएगा, और इन क्लस्टर्स के लिए प्रारंभिक रूप से **₹1,000 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड** उपलब्ध कराया जाएगा।

अक्षय **अन्न योजना** के अंतर्गत, **कम आय वर्ग के परिवारों को प्रति माह मुफ्त राशन** प्रदान किया जाएगा, जिसमें चावल, ज्वारी, मूंगफली का तेल, नमक, चीनी, हल्दी, सरसों, जीरा और लाल मिर्च पाउडर शामिल होंगे।

'महारथी (महाराष्ट्र एडवांस रोबोटिक्स और AI प्रशिक्षण हब योजना) - अटल टिंकरिंग लैब्स योजना' शुरू की जाएगी, जिससे सभी सरकारी स्कूलों में रोबोटिक्स और AI सीखने के अवसर प्रदान किया जाएंगे।

महाराष्ट्र में उद्योग की आवश्यकता के आधार पर कौशल की कमी का विश्लेषण करने के लिए **कौशल जनगणना** आयोजित की जाएगी। इससे कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराये जा सकेंगे और **आवश्यकतानुसार नए कुशल मानव संसाधन की योजना बनाई जा सकेगी।**

25 प्रमुख मुद्दे

महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले में **'छत्रपति शिवाजी महाराज आकांक्षा केंद्र'** की स्थापना की जाएगी, जिसके माध्यम से **10 लाख नए उद्यमियों का निर्माण** किया जाएगा। इन केंद्रों में **को-वर्किंग स्पेस** और **इनक्यूबेशन सुविधाएं** होंगी जहां छात्र, पेशेवर और उद्यमी आपस में जुड़ सकेंगे, नेटवर्क बना सकेंगे और नवीन विचारों को बढ़ावा दे सकेंगे।

अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के उद्यमियों के व्यवसाय वृद्धी के लिए **₹15 लाख तक ब्याजमुक्त ऋण** प्रदान किया जाएगा।

ओबीसी, एसईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एनटी, और वीजेएनटी के पात्र विद्यार्थियों को **शिक्षा शुल्क और परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति** प्रदान की जाएगी।

18 से 35 वर्ष के युवाओं की वार्षिक स्वास्थ्य जांच के लिए **स्वामी विवेकानंद युवा स्वास्थ्य कार्ड (Youth Health Card)** शुरू किया जाएगा और **नशामुक्त-व्यसनमुक्त महाराष्ट्र** के लिए स्थायी योजना लागू की जाएगी।

25 प्रमुख मुद्दे

महाराष्ट्र कई प्राचीन और ऐतिहासिक किलों का घर है, जो राज्य के गौरव के प्रतीक हैं और इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महाराष्ट्र के इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए **किला विकास प्राधिकरण (FDA)** स्थापित किया जाएगा।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्राथमिकता नीति अपनाई जाएगी, जिसमें:

a. **प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक के लिए स्वचालित सेवा** प्रदान करने के लिए आधार सक्षम सेवा वितरण (AESD) को लागू किया जायेगा।

b. **80 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों** द्वारा मांगे गए दस्तावेज– जैसे कि स्वास्थ्य रिकॉर्ड, पहचान पत्र और पेंशन संबंधित दस्तावेज–**सीधे उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था** की जाएगी।

c. सभी सरकारी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए **स्वतंत्र आउट पेशेंट डिपार्टमेंट (OPD)** स्थापित किए जाएंगे।

जबरन और धोखाधड़ी से धर्मांतरण के खिलाफ एक सख्त कानून बनाया जाएगा, जिससे जबरदस्ती और भ्रामक धार्मिक धर्मांतरण से सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।

कृषि एवं मानव बस्ती क्षेत्रों में बाघ, तेंदुआ, हाथी, नीलगाय, जंगली सूअर और बंदरों जैसे वन्यजीवों के कारण होने वाली **जान-माल की हानि को रोकने** तथा **मानव-पशु संघर्ष को कम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), ड्रोन और रेडियो कॉलर** जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रभावी उपयोग किया जाएगा।

कृषि एवं सम्बंधित क्षेत्र

हमारे संकल्प

कृषि क्षेत्र: हमारा लक्ष्य खेती में प्रतिष्ठा, सुरक्षा और समृद्धि का संचार करना है।

1. **किसानों की ऋण माफी** और किसान सम्मान योजना के अंतर्गत **वार्षिक राशि ₹12,000 से बढ़ाकर ₹15,000** की जाएगी, साथ ही **न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के समन्वय में 20% तक भावांतर** योजना लागू की जाएगी।
2. किसानों की उपज को उचित मूल्य मिले इसके लिए मुख्य रूप से **नकदी फसलों के लिए हर वर्ष नई रोपण और विपणन योजना बनाई जाएगी, जो किसानों को उनकी उपज में अधिकतम लाभ देने का कार्य करेगा।**
3. **सिंचाई: जलयुक्त शिवार अभियान 3.0, मराठवाड़ा वॉटर ग्रिड प्रोजेक्ट, नार-पार-गिरना नदी जोड़ परियोजना और नल-गंगा-वैनगंगा नदी जोड़ परियोजना** जैसी पहलों के साथ महाराष्ट्र में सिंचित क्षेत्रों का विस्तार करना तथा जल संसाधन और सिंचाई क्षमता को बढ़ाया जाएगा। प्रत्येक गांव स्तर पर **'जल बजट'** के सिस्टम को लागू किया जाएगा, साथ ही **'मागेल त्याला शेततळे'** (मांग पर खेत तालाब) योजना का विस्तार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, 'प्रति बूंद अधिक फसल' पहल को बढ़ावा देने के लिए **सूक्ष्म सिंचाई हेतु अनुदान बढ़ाया** जाएगा।
4. राज्य के 45,000 गांवों में **पांधण रास्ते बनाए जाएंगे।**
5. **डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक कृषि मिशन:** वर्ष 2029 तक जैविक खेती का क्षेत्र 10 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 25 लाख हेक्टेयर तक किया जाएगा, जिससे **दीर्घकालिक खेती पद्धतियों को प्रोत्साहन मिलेगा।** जिला और तालुका स्तर पर **जैविक खेती बाजार भी स्थापित किए जाएंगे।**
6. **संभागवार क्लस्टर बनाकर और प्रौद्योगिकी आधारित कृषि प्रबंधन के लिए पर्याप्त धनराशि** आवंटित करके महाराष्ट्र को **कृषि-तकनीक स्टार्टअप हब** में बदला जाएगा।

हमारे संकल्प

7. दूरदर्शी **'अन्नदाता से ऊर्जादाता'** पहल के अंतर्गत किसानों को **सौर ऊर्जा उत्पादन** में सक्रिय रूप से शामिल किया जाएगा, जिससे वे **ऊर्जा प्रदाता** बन जाएंगे। यह नया कार्यक्रम पूरे राज्य में **ऊर्जा उत्पादक खेतों** को बढ़ावा देने के लिए **प्रोत्साहन-आधारित अनुदान** द्वारा समर्थित **सौर पैनल-आच्छादित खेती** की शुरुआत करेगा।
8. महाराष्ट्र को **मक्का और बांस आधारित एथेनॉल का केंद्र** में बदला जाएगा, जिससे सतत ऊर्जा उत्पादन, स्थानीय कृषि को सहायता और लक्षित प्रोत्साहनों के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ।
9. किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त **कमाई के रूप में मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित** किया जाएगा। पारंपरिक कृषि पद्धतियों के साथ-साथ **मधुमक्खी पालन को अपनाने में एक लाख किसानों की सहायता** के लिए प्रशिक्षण और प्रचार कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।
10. किसानों की आय बढ़ाने के लिए हम निम्नलिखित व्यापक पहल लागू करेंगे:
    a. किसानों को खरीदे गए उर्वरकों पर चुकाए गए **सम्पूर्ण राज्य माल एवं सेवा कर (एसजीएसटी) पर छूट मिलेगी,** जो उन्हें सब्सिडी के रूप में वापस कर दी जाएगी।
    b. यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को **सोयाबीन के लिए प्रति क्विंटल ₹6,000 का न्यूनतम मूल्य मिले,** हम सोयाबीन उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के लिए एक समर्पित मूल्य श्रृंखला स्थापित करेंगे।

11. **फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान** को रोकने और बाजार में अनुकूल कीमतों पर पहुंचने तक **फसल की गुणवत्ता बनाए** रखने के लिए, हम ग्रामीण महाराष्ट्र में **सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज और स्मार्ट पैकेजिंग सुविधाएं** विकसित करने के लिए **'कृषि संकलन कोष'** की स्थापना करेंगे।
12. कपास की कटाई और प्रसंस्करण को उन्नत तकनीक के साथ आधुनिक बनाया जाएगा। इसके तहत **'कपास से कपड़े' तक की मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के उपाय किए जाएंगे, जिससे किसानों और कपड़ा उद्योग को आर्थिक लाभ मिलेगा।**
13. महाराष्ट्र को एक **प्रमुख दलहन उत्पादक क्षेत्र** के रूप में स्थापित किया जाएगा, राज्य को 2027 तक दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए **ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसंस्करण केंद्र** स्थापित किए जाएंगे।

14. कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए **बड़े पैमाने पर पैकिंग हाउस स्थापित किए जाएंगे,** ताकि **भंडारण और प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाई जा सके** और निर्यातोन्मुखी फसल उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। ये **केंद्र पैकिंग और प्रसंस्करण में प्रशिक्षण प्रदान करेंगे,** व्यावसायिक कौशल बढ़ाएंगे और रोजगार के अवसर पैदा करेंगे।

15. **प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र** तहत **सतत कृषि पद्धतियों** को बढ़ावा देंगे, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी।

16. **प्याज के उचित मूल्य सुनिश्चित करने** के लिए एक **व्यापक नीति** लागू की जाएगी। **प्याज उत्पादन पंजीकरण के लिए एक 'प्याज पोर्टल'** शुरू किया जाएगा और प्याज की कीमतों को स्थिर बनाए रखने के लिए एक **'बाजार स्थिरीकरण कोष'** स्थापित किया जाएगा। प्याज की शीघ्र खराब होने वाली क्षमता को देखते हुए, **प्याज भंडारण और प्रसंस्करण क्लस्टर** विकसित करने के लिए **प्रोत्साहन** प्रदान किए जाएंगे।

17. **प्रत्येक जिले में वार्षिक शेतकरी प्रगति महोत्सव** का आयोजन किया जाएगा, जिसमें **महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष रूप से दो दिवसीय कृषि प्रशिक्षण सत्र** आयोजित किए जाएंगे। इस महोत्सव में प्रदर्शनी में निःशुल्क प्रवेश, आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों का जीवंत प्रदर्शन, तथा विविध कृषि हितधारकों के बीच विचारों के आदान-प्रदान के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।

18. कृषि उत्पादन और कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए **'यांत्रिक कृषि' मिशन (कृषि मशीनीकरण मिशन)** की शुरुआत की जाएगी, जिसमें:

    a. **किसानों को कृषि मशीनीकरण के ज्ञान से प्रशिक्षित** किया जाएगा।

    b. **उत्पादन व्यय को कम करने हेतु ड्रोन तकनीक का उपयोग** करके कृषि निवेश की लागत में कमी लाने के प्रयास किए जाएंगे।

19. कृषि उपज के लिए **उचित बाजार पहुंच और मूल्य सुनिश्चित करने के लिए,** कृषि उपज बाजार समितियों (एपीएमसी) को सूचना

प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिक बनाया जाएगा।

20. **किसान उत्पादक संगठनों (FPOs)** के लिए **व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम** आयोजित किए जाएंगे, जिससे उनके कौशल में वृद्धि होगी और उपलब्ध प्रोत्साहनों और निधियों का समुचित उपयोग किया जा सकेगा।

21. **किसान उत्पादक संगठनों (FPOs)** को तकनीकी और व्यावसायिक दृष्टि से अधिक सक्षम बनाने के लिए, उनके उत्पादन से संबंधित **नामांकित निजी उद्योगों के साथ संलग्न करने की नीति** अपनाई जाएगी।

22. नागपुर के मिहान में **संतरा पल्प**, जलगांव और नांदेड़ में **केला प्रसंस्करण संयंत्र** स्थापित की जाएंगी।

सहकार

23. हाल के समय में ग्रामीण क्षेत्रों और कृषि क्षेत्र में बदलते रुझानों को ध्यान में रखते हुए, **जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCBs) और प्राथमिक सहकारी समितियों (PACs)** की कार्यक्षमता, पारदर्शिता, सुशासन और व्यावसायिकता को **मजबूत करने के लिए आवश्यक बदलाव किए जाएंगे।**

24. **चीनी और कपास सहकारी समितियों के लिए आधुनिक नीतियां तैयार की जाएंगी** ताकि उन्नत प्रौद्योगिकी और बेहतर प्रबंधन पद्धतियों के माध्यम से उन्हें अधिक स्पर्धात्मक और प्रभावी बनाया जाएगा।

25. **नई सहकारी समितियों** के गठन के लिए **एकल खिड़की प्रणाली स्थापित की जाएगी,** जिसमें **ऑनलाइन आवेदन और ट्रैकिंग प्रणाली** शामिल होगी, जिसके परिणामस्वरूप इस प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और अनुमोदन प्रक्रिया तेज होगी।

26. सहकारी संस्थाओं में एक व्यापक **हरित ऊर्जा कार्यक्रम** शुरू किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित पहल शामिल होंगी:

    a. सहकारी चीनी मिलों में **इथेनॉल भंडारण क्षमता बढ़ाने** के लिए अनुदान।

    b. बायो-सीएनजी, सौर ऊर्जा और हाइड्रोजन परियोजनाओं की स्थापना के लिए **1:2 के अनुपात में इक्विटी फंडिंग** की व्यवस्था।

c. कृषि बायोमास का उपयोग करके ब्रिकेटिंग और पेलेटाइजिंग यूनिट्स स्थापित करने के लिए **50% अनुदान**।

d. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के माध्यम से **हरित ऊर्जा परियोजनाओं की परिचालन लागत** के लिए **सब्सिडीयुक्त वित्तपोषण**।

e. **हरित ऊर्जा अवसंरचना पर पूंजीगत व्यय के लिए ब्याज में छूट।**

27. सहकारी समितियों को चीनी क्षेत्र के बाहर **फसल आधारित कृषि प्रसंस्करण इकाइयां** स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा:

a. प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए **1:2 अनुपात में इक्विटी फंड** की व्यवस्था।

b. सहकारी संस्थाओं में कृषि प्रसंस्करण इकाइयों के **परिचालन खर्च के लिए रियायती दरों पर वित्तीय सहायता।**

मत्स्यपालन

28. **'महाराष्ट्र मत्स्य मिशन'** शुरू करके **2030 तक मछली उत्पादन को दोगुना करने की योजना** बनाई जाएगी, इसके अंतर्गत:

a. **कोल्ड स्टोरेज, बायोफ्लॉक, केज फिश फार्मिंग** जैसी बुनियादी सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा।

b. मछली उत्पादन के लिए अनुकूल बाजार मूल्य सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत **बाजार संपर्क श्रृंखला विकसित की जाएगी।**

29. महाराष्ट्र को **देश का प्रमुख झींगा उत्पादक राज्य** बनाने हेतु, छोटे और बड़े जलाशयों में झींगा उत्पादन को बढ़ावा देंगे, इसके लिए:

a. झींगा उत्पादन में संलग्न मत्स्य किसानों के **सतत आर्थिक विकास** हेतु तकनीकी सहायता केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण और समर्थन प्रदान किया जाएगा।

b. झींगा कृषि के लिए **बीमा सुरक्षा योजना** शुरू की जाएगी।

30. **मत्स्य सहकारी समितियों** को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, प्रसंस्करण और विपणन का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करके सशक्त बनाया जाएगा, जिससे महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र के **मछुआरों की आजीविका में बढ़ोत्तरी होगी।**

पशुपालन

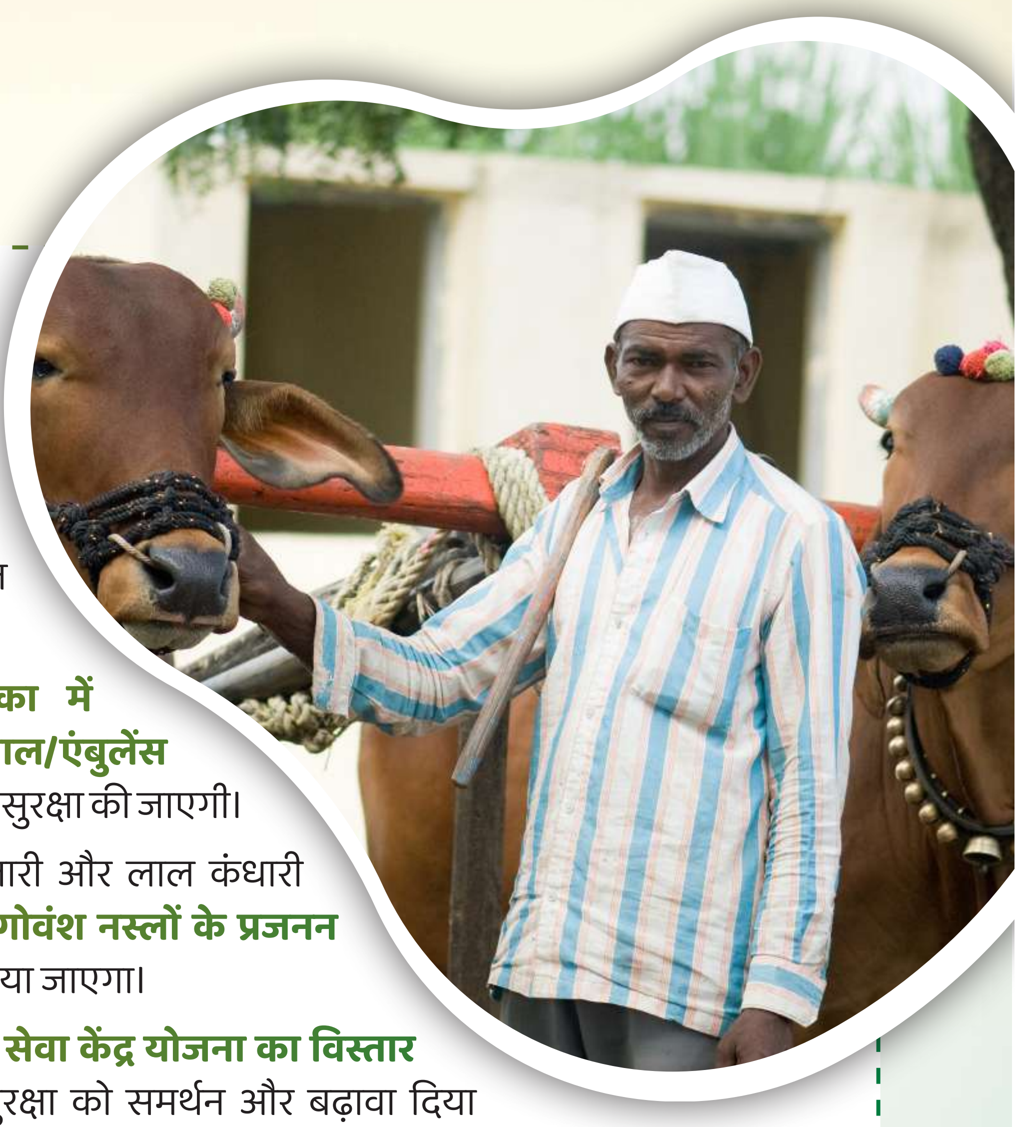

31. **'महाराष्ट्र दुग्ध विकास मिशन'** शुरू कर **2030 तक दुग्ध उत्पादन क्षमता को 300 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाकर** दुग्ध प्रसंस्करण उद्योग और बिक्री को प्रोत्साहित किया जाएगा।

32. महाराष्ट्र के **प्रत्येक तालुका में चलित पशु चिकित्सा अस्पताल/एंबुलेंस** प्रदान कर राज्य के पशुधन की सुरक्षा की जाएगी।

33. डांगी, देवनी, गवळाऊ, खिल्लारी और लाल कंधारी जैसी **महाराष्ट्र की स्थानीय गोवंश नस्लों के प्रजनन और पोषण** को प्रोत्साहित किया जाएगा।

34. पूर्व में लागू **गोवर्धन - गोवंश सेवा केंद्र योजना का विस्तार** कर गाय की संरक्षण और सुरक्षा को समर्थन और बढ़ावा दिया जाएगा।

अर्थव्यवस्था और उद्योग

हमारे संकल्प

भारत का विकास इंजन

1. **2028 तक महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था** बनाने का लक्ष्य है।

2. **उद्यम सुलभता अधिनियम** (Ease of Doing Business Act) लागू किया जाएगा।

3. महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले में **'छत्रपति शिवाजी महाराज आकांक्षा केंद्र'** की स्थापना की जाएगी, जिसके माध्यम से **10 लाख नए उद्यमियों का निर्माण** किया जाएगा। इन केंद्रों में **को-वर्किंग स्पेस** और **इनक्यूबेशन सुविधाएं** होंगी जहां छात्र, पेशेवर और उद्यमी आपस में जुड़ सकेंगे, नेटवर्क बना सकेंगे और नवीन विचारों को बढ़ावा दे सकेंगे।

4. महाराष्ट्र को प्रौद्योगिकी, उत्पादन और नवीन विचारों के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे:

   a. **'मेक इन महाराष्ट्र' नीति** के कार्यान्वयन से महाराष्ट्र को भारत के प्रमुख उत्पादन राज्य के रूप में मज़बूती से स्थित और सशक्त किया जाएगा।

   b. महाराष्ट्र को **फिनटेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की वैश्विक राजधानी** के रूप में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए वैश्विक फिनटेक कंपनियों को आकर्षित करने वाला अनुकूल वातावरण बनाया जाएगा और आर्थिक प्रौद्योगिकी में नई संकल्पनाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके साथ ही AI अनुसंधान, नवाचार और विकास को बढ़ावा देने के लिए देश का पहला समर्पित **AI विश्वविद्यालय** की स्थापना की जाएगी।

   c. नागपुर, पुणे, छत्रपति संभाजीनगर, अहिल्यानगर और नासिक को **आधुनिक एयरोनॉटिकल और स्पेस उत्पादन केंद्र** बनाकर एक उन्नत एयरोस्पेस प्रौद्योगिकी और उत्पादन हब के रूप में विकसित किया जाएगा।

हमारे संकल्प

5. जलगांव, अमरावती, नांदेड़ और सोलापुर को उदयोन्मुख उद्योगों के लिए **नए औद्योगिक जिले** के रूप में स्थापित किया जाएगा।

6. **नासिक को महाराष्ट्र का अगला आईटी हब** बनाने के लिए प्रस्तावित आईटी पार्क को पूर्ण कर विश्व-स्तरीय सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

7. भारत की सबसे बड़ी रक्षा परियोजना, **विदर्भ-मराठवाड़ा रक्षा सर्किट कॉरिडोर** की स्थापना की जाएगी, जिसका प्रभाव महाराष्ट्र के 12 जिलों पर पड़ेगा और उल्लेखनीय रोजगार के अवसर पैदा करेगा।

8. **सोलापुर में फूड पार्क की स्थापना की जाएगी** और **शेंगाचटनी जैसे स्थानीय रेडी-टू-ईट और रेडी-टू-कुक उत्पादों** को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

औद्योगिक प्रोत्साहन

9. **'एक जिला एक उत्पाद' (ओ.डी.ओ.पी)** योजना के तहत **प्रत्येक मॉल में तीन स्टॉल आरक्षित किये जाएंगे** जहाँ महाराष्ट्र के स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन मिलेगा।

10. फल, फूल एवं सब्जी विक्रेताओं और ठेलों पर विभिन्न व्यवसाय करने वाले छोटे कारोबारियों को **आर्थिक प्रोत्साहन** दिया जाएगा।

11. **विदर्भ में 32 बंद कोयला खदानों** को कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के लिए पुनः उपयोग में लाया जाएगा।

12. चंद्रपुर जिले में वर्तमान में स्थित **फेरो अलॉय प्लांट का विस्तार** किया जाएगा।

13. क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए अमरावती जिले में 1,000 एकड़ में **पीएम मित्र पार्क** परियोजना को गति दी जाएगी।

14. परभणी जिले में एक **मेगा टेक्सटाइल पार्क** स्थापित किया जाएगा, जिसमें फाइबर निष्कर्षण, कताई, बुनाई, रंगाई, प्रिंटिंग और वस्त्र निर्माण जैसी सम्पूर्ण कपड़ा सम्बंधित मूल्य श्रृंखला शामिल होंगी।

15. नासिक जिले में एक **खिलौना उत्पादन क्लस्टर** स्थापित कर नासिक को देश के सबसे बड़े खिलौना उत्पादन केंद्र में परिवर्तित किया जाएगा।

16. केंद्र सरकार के कॉयर बोर्ड की मदद से **उत्तरी कोंकण में कॉयर उद्योग के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। महाराष्ट्र काथा नीति का विस्तार किया जाएगा,** और हर वर्ष **'कोंकण नारियल एवं काथा महोत्सव'** का आयोजन किया जाएगा।

17. **कोल्हापुरी चप्पल निर्माण उद्योग** को प्रोत्साहन देकर इसके निर्यात को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

18. सांगली में **हल्दी पार्क** की स्थापना कर GI-टैग वाली सांगली की हल्दी और मसालों को सरकारी ब्रांडिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) को प्रोत्साहन

19. संतुलित औद्योगिक विकास के लिए **मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्कों (MMLP)** की स्थापना की जाएगी।

20. स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए **एमआईडीसी क्षेत्र में भूखंडों के आवंटन** में उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।

21. **जालना में प्लग-एंड-प्ले सुविधा** के साथ एमएसएमई (MSME) पार्क स्थापित किया जाएगा।

22. **गडचिरोली** और **चंद्रपुर** जिलों में बांस शिल्पकारों को उनके **उद्यमिता कौशल** को बढ़ावा देने के लिए बांस अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से **प्रशिक्षण** और **प्रमाणन** प्रदान किया जाएगा।

शिक्षा

हमारे संकल्प

1. ग्रामीण छात्रों के लिए कला, संगीत और खेल क्षेत्र में उचित मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु **बालभवन की तर्ज पर स्वातंत्र्यवीर सावरकर कला और खेल संकुल** स्थापित किए जाएंगे।
2. **डिजिटल शिक्षा सशक्तिकरण कार्यक्रम (DEEP)** आरंभ किया जाएगा, जिसके अंतर्गत:
   a. सभी सरकारी स्कूलों में **अत्याधुनिक कंप्यूटर प्रयोगशालाएं** स्थापित की जाएंगी और प्रत्येक स्कूल को इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
   b. **विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और गणित (STEM)** शिक्षा में **इंटरैक्टिव शिक्षण विधियों** को लागू किया जायेगा।
   c. **'नई शिक्षा नीति (NEP) 2020'** के अंतर्गत कंप्यूटर भाषा सीखने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा।
   d. प्रत्येक सरकारी स्कूल में **'महाविद्या' नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) शिक्षा प्रणाली** लागू की जाएगी।
3. सभी मौजूदा आंगनवाड़ियों की नई पीढ़ी को **'सक्षम आंगनवाड़ियों'** में अपग्रेड किया जाएगा।
4. प्रत्येक जिले में अति आधुनिक **कर्मवीर भाऊराव पाटील आदर्श मराठी स्कूल (मॉडल कंपोजिट स्कूल)** स्थापित किए जाएंगे, जिसमें प्री-प्राइमरी से 12वीं कक्षा तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसमें शामिल होगा:
   a. **10 एकड़ का विस्तृत परिसर, स्मार्ट क्लासरूम** और रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग एवं डिजिटल कौशल के लिए अत्याधुनिक प्रयोगशालाएँ।
   b. **छात्रों के लिए निवास सुविधा** और सभी सुविधाओं से युक्त खेल परिसर।

हमारे संकल्प

5. **'सीएम श्री योजना'** शुरू करने से **उन मराठी स्कूलों के लिए शैक्षणिक सुविधाओं में सुधार किया जाएगा, जिन्हें पीएम श्री योजना में शामिल नहीं किया जा सका,** जिससे उनके बुनियादी ढांचे और आधुनिक शैक्षणिक सुविधाओं में वृद्धि की जा सके।

6. कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण से परिचित कराने के लिए स्थानीय संगठनों एवं तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों के सहयोग से स्कूली शिक्षा में **वर्तमान कार्य-अनुभव से जुड़े विषयों का विस्तार किया जाएगा।**

7. ओबीसी, एसईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एनटी, और वीजेएनटी के पात्र विद्यार्थियों को **शिक्षा शुल्क और परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति** प्रदान की जाएगी।

8. नैना परियोजना के तहत नवी मुंबई क्षेत्र में **'एडु-सिटी'** की स्थापना की जाएगी, जिसे 'तीसरी मुंबई' के रूप में विकसित किया जा रहा है। इससे विश्वस्तरीय शैक्षणिक संस्थानों को बढ़ावा मिलेगा।

9. **समुद्र विज्ञान और मत्स्य पालन के लिए एक स्वतंत्र विश्वविद्यालय** स्थापित किया जाएगा।

10. **औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs)** का आधुनिकीकरण किया जाएगा, साथ ही पाठ्यक्रमों का नवीनीकरण किया जाएगा, जिसमें **ऑगमेंटेड रियलिटी (AR), वर्चुअल रियलिटी (VR), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML)** जैसे विषय शामिल किए जाएंगे। इसके साथ ही, आवश्यकतानुसार ITI की संख्या में वृद्धि की जाएगी।

युवा और खेल

हमारे संकल्प

युवा सशक्तिकरण

1. **छत्रपति संभाजी महाराज युवा नेतृत्व प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत 10,000 युवाओं** को राजनीतिक और सार्वजनिक नेतृत्व का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
2. 18 से 35 वर्ष के युवाओं की वार्षिक स्वास्थ्य जांच के लिए **स्वामी विवेकानंद युवा स्वास्थ्य कार्ड (Youth Health Card)** शुरू किया जाएगा और **नशामुक्त-व्यसनमुक्त महाराष्ट्र** के लिए स्थायी योजना लागू की जाएगी।
3. **राज्य सरकार की भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाने** के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए जाएंगे।
4. भर्ती प्रक्रिया के लिए आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अलग-अलग शुल्क लेने के बजाय, **एक ही वार्षिक शुल्क लागू किया जाएगा।** यह शुल्क उचित होगा और उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के आधार पर परीक्षा में बैठने की अनुमति देगा।

कौशल विकास

5. पारंपरिक कौशलों को मान्यता और प्रोत्साहन देने के लिए **कारीगर विश्वविद्यालय** की स्थापना की जाएगी।
6. **'महारथी (महाराष्ट्र एडवांस रोबोटिक्स और AI प्रशिक्षण हब योजना) - अटल टिंकरिंग लैब्स योजना'** शुरू की जाएगी, जिससे सभी सरकारी स्कूलों में रोबोटिक्स और AI सीखने के अवसर प्रदान किया जाएंगे।

हमारे संकल्प

7. **शिल्पकला में पारंपरिक हस्तकला के संरक्षण और कौशल विकास** को प्रोत्साहित करने के लिए **'लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे कलाग्राम'** स्थापित किया जाएगा। यह कारीगरों को **विशेष प्रशिक्षण और उन्हें आधुनिक बाजार में सफल होने के लिए आवश्यक साधन** उपलब्ध कराएगा।

8. महाराष्ट्र में उद्योग की आवश्यकता के आधार पर कौशल की कमी का विश्लेषण करने के लिए **कौशल जनगणना** आयोजित की जाएगी। इससे कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराये जा सकेंगे और **आवश्यकतानुसार नए कुशल मानव संसाधन की योजना बनाई जा सकेगी।**

रोजगार

9. हम पूरे महाराष्ट्र में **10 लाख छात्रों** को उनकी शिक्षा समर्थन के लिए और परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए **₹10,000 का मासिक मानदेय** प्रदान करेंगे। साथ ही राज्य में **25 लाख रोज़गार के अवसर** उपलब्ध कराएंगे।

10. **11,000 शिक्षकों की भर्ती** की गई है और बाकी सभी रिक्तियों को भरने के लिए **'महाभर्ती अभियान'** शुरू किया जाएगा।

11. महाराष्ट्र के युवाओं के लिए **एक ओवरसीज प्लेसमेंट सेल** की स्थापना की जाएगी, जो अन्य देशों और फॉर्च्यून 500 कंपनियों के साथ सरकार-से-सरकार (G2G) समझौतों के माध्यम से **ग्रेड C और D** पदों के लिए नौकरी पंजीकरण की सुविधा प्रदान करेगा। यह पहल महाराष्ट्र के युवाओं को वैश्विक रोजगार के अवसर प्रदान करेगी।

12. **स्टार्टअप सीड फंडिंग के लिए एक अलग कोष आवंटित किया जाएगा,** जिससे नए उद्यमियों और उनके नवाचारों को प्रोत्साहन मिलेगा।

13. राज्य भर में **50 अत्याधुनिक कला स्टूडियो स्थापित** किए जाएंगे, जिससे कंटेंट क्रिएटर्स को उच्च गुणवत्ता वाले कंटेंट बनाने के लिए संसाधन और आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी।

14. **प्रतियोगी परीक्षा में लिखित परीक्षा पास करने वाले, परंतु चयनित न होने वाले परीक्षार्थियों** के लिए **एक वैकल्पिक प्लेसमेंट योजना** लागू की जाएगी, जिससे वे अपने ज्ञान का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकें।

खेल

15. महाराष्ट्र के प्रत्येक संभाग में **महाराष्ट्र ओलंपिक प्रशिक्षण अकादमी** स्थापित की जाएगी, जिससे राज्य के खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त करने में सहायता प्रदान की जा सके।

16. महाराष्ट्र में **खेल संस्कृति की वृद्धि** के लिए आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी:

    a. महाराष्ट्र भर में **'खेलो इंडिया' की तर्ज पर 'खेलो महाराष्ट्र' कार्यक्रम** शुरू किया जाएगा, जिसके माध्यम से स्थानीय प्रतिभाओं की पहचान और विकास में सहायता मिलेगी।

    b. खिलाड़ियों को **समावेशी स्वास्थ्य बीमा और स्वास्थ्य कार्ड** उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उन्हें मुफ्त चिकित्सा जांच और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएँ मिलेंगी।

    c. राज्य के सभी महाविद्यालयों में **खेल विज्ञान स्नातक पाठ्यक्रम** शुरू करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिससे बड़ी संख्या में कुशल प्रशिक्षक, फिजियोथेरेपिस्ट और खेल प्रबंधक उपलब्ध होंगे।

    d. **'गाँव तिथे क्रीड़ा केंद्र'** योजना शुरू करके सभी जिला परिषद स्कूलों में खेल संकुल स्थापित किए जाएंगे।

17. स्थानीय स्तर पर लोकप्रिय खेलों के आधार पर **जिलों को खेल केन्द्रों** के रूप में विकसित करने के लिए:

    a. **कोल्हापुर** को **फुटबॉल का केंद्र** बनाने के लिए वहां एक विश्वस्तरीय स्टेडियम बनाया जाएगा।

    b. **नांदेड़ में अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम** का निर्माण कर हॉकी के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त की जाएगी।

18. हम पुणे, नागपुर, नासिक और छत्रपति संभाजीनगर में **अत्याधुनिक ई-स्पोर्ट्स क्षेत्र एवं प्रशिक्षण केंद्र** स्थापित करेंगे, जो अत्याधुनिक तकनीकों से सुसज्जित होंगे।

PARIS 2024
JSW
Inspire
INDIA

स्वास्थ्य

हमारे संकल्प

सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवाएँ

1. **'मिशन स्वस्थ महाराष्ट्र'** के अंतर्गत राज्य की **सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं** का विकास किया जाएगा, जिसमें:

   a. हाल के समय में बढ़ती स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, महाराष्ट्र के **चिकित्सा, नर्सिंग और मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नॉलॉजी (DMLT)** से सम्बंधित डिग्री कॉलेजों में **छात्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी।**

   b. **आयुष्यमान भारत** और **महात्मा फुले जन स्वास्थ्य योजना** के तहत सभी को **₹5 लाख तक** मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाएगा।

   c. प्रत्येक **प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र** और **स्वास्थ्य उपकेंद्र** में **पीएम जन औषधि केंद्र** स्थापित किए जाएंगे, ताकि लोगों को **सस्ती दरों पर औषधियाँ** उपलब्ध हो सकें।

2. **आयुष्मान भारत योजना** के अंतर्गत **शामिल अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जाएगी,** जिससे लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवाएँ सुगमता से उपलब्ध होंगी और बेहतर उपचार विकल्प सुनिश्चित हो सके।

3. **एम्स नागपुर** और आगामी **एम्स पुणे** के सहयोग से पूरे महाराष्ट्र में **टेली-कंसल्टेशन सेवा** प्रदान की जाएगी।

4. **उच्च रक्तचाप, मधुमेह और मोटापे जैसी जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों** के लिए **मुफ्त जांच और दवा उपलब्ध** कराई जाएगी।

5. **आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY)** के तहत **वरिष्ठ नागरिकों** और **महिलाओं** के लिए प्रत्येक उपकेंद्र पर **हर छह महीने में मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर** आयोजित किए जाएंगे।

स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना

6. नागपुर और नांदेड़ में **24 अस्पताल भवनों** वाले धन्वंतरि और गोदावरी मेडिसिटी की स्थापना की जाएगी। इन सुविधाओं की कुल क्षमता **10,000 बिस्तरों की होगी और सभी सुपर-स्पेशलिटी अस्पताल** एक ही स्थान पर मिलेंगे।
7. **महिलाओं और बच्चों के लिए उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं:** महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि की जाएगी तथा सभी जिलों में **मातृत्व और नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवाओं से सुसज्जित महिला एवं बाल अस्पताल उपलब्ध** कराए जाएंगे।
8. सन **2047 तक महाराष्ट्र से सिकल सेल एनीमिया का सम्पूर्ण उन्मूलन** करने का संकल्प लिया गया है। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे:
    a. **स्क्रीनिंग केन्द्रों** की स्थापना, गर्भवती महिलाओं को जांच की सुविधा, तथा सिकलसेल पहचान कार्ड का वितरण।
    b. आवश्यकता अनुसार **सिकल सेल एनीमिया अनुसंधान केंद्रों** की स्थापना।
9. महाराष्ट्र में **रक्त आपूर्ति सेवा का विस्तार** किया जाएगा, जिससे **थैलेसीमिया रोगियों** को समय पर पर्याप्त मात्रा में रक्त उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त, **थैलेसीमिया पर आधुनिक और प्रभावी उपचार** पर रिसर्च के लिए **समर्पित अनुसंधान संस्थान** स्थापित किए जाएंगे।
10. **साल 2029 तक** प्रत्येक तालुका के ग्रामीण **अस्पतालों का आधुनिकीकरण** किया जाएगा, जिसमें **दो बेड का डायलिसिस यूनिट, चार बेड की ICU** और **एक ऑपरेशन थिएटर** जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
11. **क्षय रोग मुक्त महाराष्ट्र** बनाने और **मोतियाबिंद निवारण** के लिए प्रत्येक जिले में **मासिक मुफ्त निदान और उपचार शिविर** आयोजित किए जाएंगे।

12. हाल के समय में **कैंसर के मामलों में वृद्धि** हो रही है। **जल्दी जांच** होने पर **कैंसर पर विजय** पाई जा सकती है। इसलिए, तालुका स्तर पर **निःशुल्क कैंसर जांच की सुविधा उपलब्ध होगी** तथा प्रत्येक जिले में **अत्याधुनिक कैंसर निदान प्रयोगशालाएं** स्थापित की जाएंगी।

13. **जनजातीय क्षेत्रों के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में एक मेडिकल मोबाइल यूनिट होगी** जो दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगी, जिससे दूर के जनजातीय क्षेत्रों में अंतिम छोर तक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना सुनिश्चित किया जायेगा।

14. महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले में **डिजिटल डी-एडिक्शन सेंटर** शुरू किया जाएगा, जिसमें **स्मार्टफोन, ऑनलाइन जुआ और गेमिंग** जैसे नई पीढ़ी की आदतों पर नियंत्रण रखने में सहायता मिलेगी।

आयुष आरोग्य महाराष्ट्र

15. महाराष्ट्र की रोग उपचारण प्रणाली में आयुष उपचार पद्धतियों को शामिल किया जाएगा और उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा।

    a. **AYUSH - आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी** का विनियमन और संवर्धन लागू किया जाएगा और इसके लिए एक **स्वतंत्र प्रणाली स्थापित** की जाएगी।

    b. प्रत्येक तालुका स्तर पर अस्पताल में चरणबद्ध तरीके से **'आयुष' आरोग्य सेवाएं** उपलब्ध कराई जाएंगी।

16. महाराष्ट्र में आयुर्वेद के अनुसंधान, शिक्षा और उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए **अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान** के समान राज्य सरकार द्वारा एक शीर्ष संस्था की स्थापना की जाएगी।

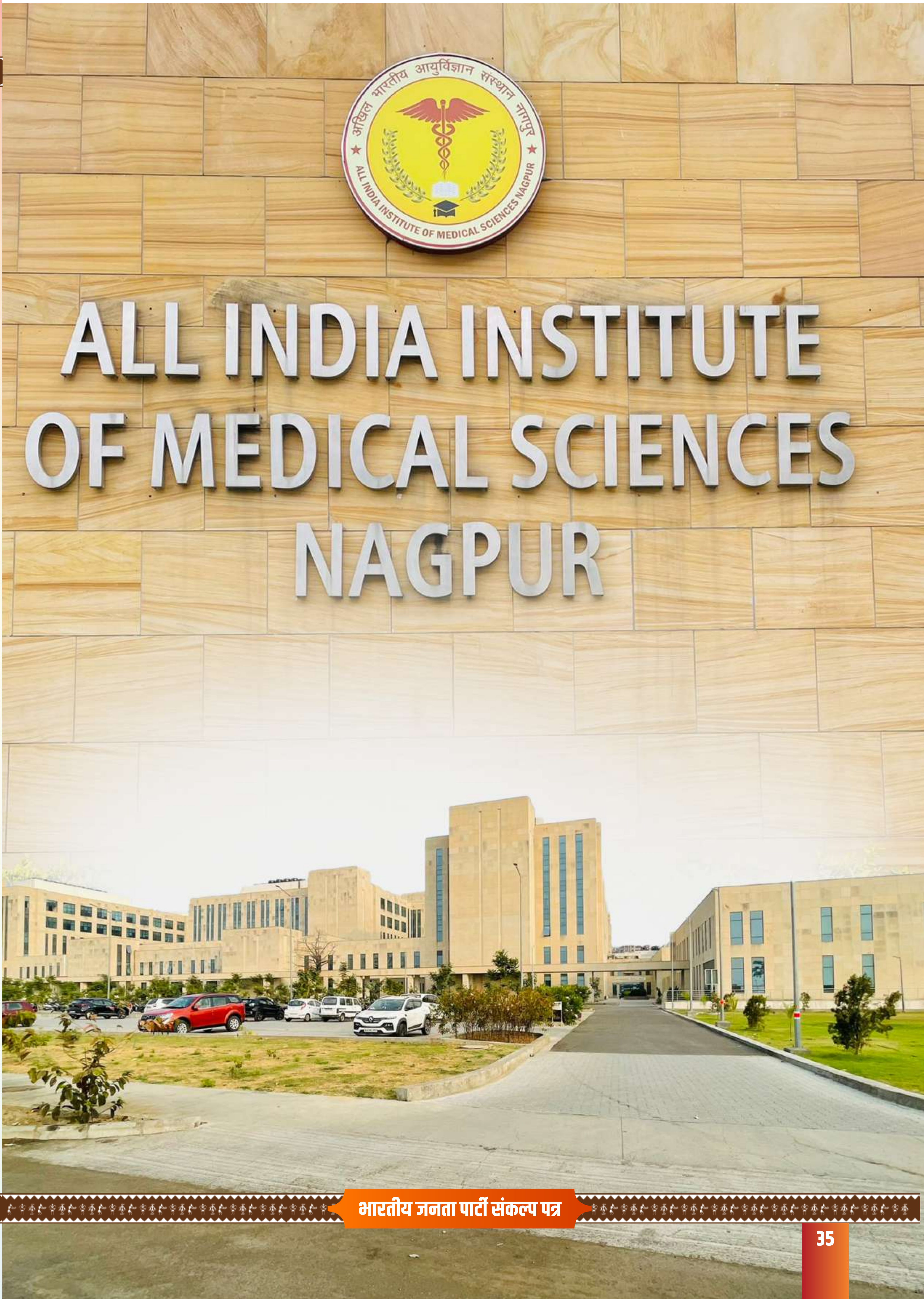
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नागपुर
ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES NAGPUR
ALL INDIA INSTITUTE
OF MEDICAL SCIENCES
NAGPUR

महिला सम्मान

राज्य में सभी महिलाओं के लिए सुरक्षा, सम्मान और समान अवसर सुनिश्चित करना हमारा उद्देश्य है।

हमारे संकल्प

महिला आत्मनिर्भरता

1. हम **लाड़की बहिन योजना** के अंतर्गत प्रति महिला को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को **₹1,500 से ₹2,100 तक बढ़ाएंगे** इसके अलावा, उनकी वित्तीय स्वतंत्रता को मजबूत करने हेतु वित्तीय साक्षरता का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा, और पूरे महाराष्ट्र में **25,000** महिलाओं को **पुलिस बल में भर्ती** करेंगे।
2. हम **आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा सेवकों** की आर्थिक सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें **₹15,000 का मासिक मानदेय** और बीमा कवरेज देंगे।
3. **मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना** के अंतर्गत, **प्रत्येक परिवार को वर्ष भर में तीन गैस सिलेंडर मुफ्त प्रदान किए जाएंगे।** इस योजना में आगे भी **निरंतरता** बनाई रखी जाएगी।

परिवर्तनकारी महिलाएं

4. वर्ष 2027 तक महाराष्ट्र में **50 लाख 'लखपति दीदियों'** का सृजन किया जाएगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर **500 स्वयं सहायता समूहों के लिए एक औद्योगिक क्लस्टर स्थापित** किया जाएगा, और इन क्लस्टर्स के लिए प्रारंभिक रूप से **₹1,000 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड** उपलब्ध कराया जाएगा।
5. महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र बनाने में UMED (महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियान) के महत्व को ध्यान में रखते हुए **UMED को सशक्त किया जाएगा।**
6. महिला उद्यमियों और महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए **स्थायी बाजार स्थापित किए जाएंगे** और प्रत्येक जिले में वार्षिक **'कर्मयोगिनी सम्मेलन'** आयोजित किया जाएगा।

हमारे संकल्प

7. महाराष्ट्र में **महिला स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने के लिए** निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे:
   a. महिलाओं के **स्वयं सहायता समूहों को MSME में उन्नत करने के लिए ₹10 लाख** तक के ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
   b. महिला उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन देने के लिए **MUDRA योजना के अंतर्गत ब्याज-मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।**
   c. **महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों का डिजिटलीकरण** कर बैंकों के साथ मजबूत संबंध स्थापित किये जायेंगे ताकि ऋण प्राप्त करना सुगम हो सके।
   d. प्रत्येक जिले और **शहरी सहकारी बैंकों में महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए समर्पित कक्ष स्थापित किए जाएंगे।**

महिला सम्मान, सुरक्षा और सुविधा

8. **'राजमाता जिजाऊ मातृ वंदना पुरस्कार'** प्रारंभ किया जाएगा, जिसके माध्यम से **सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्र** में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को **सम्मानित** किया जाएगा।
9. प्रत्येक जिला मुख्यालय में ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली महिला **छात्राओं** और **महिला व्यवसायियों** के लिए **अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्था** वाली **अहिल्याबाई होलकर महिला हॉस्टल** स्थापित किए जाएंगे, जिनमें उनकी शिक्षा और व्यवसायिक गतिविधियों के लिए पूरी व्यवस्था होगी।
10. मुंबई में शुरू की गई **अत्यंत सफल और प्रख्यात तेजस्विनी बसों** के आधार पर, प्रमुख शहरों में महिला यात्रियों के लिए **विशेष बस सेवाएं शुरू की जाएंगी।** यह सेवाएं विशेष रूप से व्यस्त समय में संचालित होंगी, ताकि महिला यात्रियों की सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित की जा सके।
11. **सभी शैक्षणिक संस्थानों** में **छात्राओं और महिलाओं** के प्रति **उत्पीड़न और भेदभाव** को रोकने के लिए **विशाखा समितियों** की स्थापना की जाएगी।

सामाजिक न्याय

हमारे संकल्प

वरिष्ठ नागरिक कल्याण

1. **वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्राथमिकता** नीति अपनाई जाएगी, जिसमें:
    a. **प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक के लिए स्वचालित सेवा** प्रदान करने के लिए आधार सक्षम सेवा वितरण (AESD) को लागू किया जायेगा।
    b. **80 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों** द्वारा मांगे गए दस्तावेज—जैसे कि स्वास्थ्य रिकॉर्ड, पहचान पत्र और पेंशन संबंधित दस्तावेज—**सीधे उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था** की जाएगी।
    c. सभी सरकारी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए **स्वतंत्र आउट पेशेंट डिपार्टमेंट (OPD)** स्थापित किए जाएंगे।
2. हम **वृद्धावस्था पेंशन** को **प्रति माह ₹1,500 से ₹2,100 तक बढ़ाएंगे**, जिससे पूरे महाराष्ट्र में वरिष्ठ नागरिकों को अधिक आर्थिक सुरक्षा और सम्मान मिलेगा।
3. तालुका स्तर पर, **'आजी आजोबा पार्क'** स्थापित किए जाएंगे, जिससे वरिष्ठ नागरिकों के लिए **विश्राम स्थलों की उपलब्धता** होगी।

दिव्यांग कल्याण

4. राज्य के प्रत्येक जिले में **दिव्यांग जनों के लिए कौशल मूल्यांकन, व्यावसायिक मार्गदर्शन और आर्थिक स्वावलंबन** हेतु सुविधाएँ प्रदान करने वाले **दिव्यांग भवन का निर्माण** किया जाएगा।
5. इन दिव्यांग भवनों में समाज में दिव्यांगों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता बढ़ाने वाले **दिव्यांग संवेदनशीलता कक्ष शामिल की जाएँगी**, साथ ही आवश्यकताओं के अनुसार विशेष देखभाल प्रदान करने के लिए **विशेष उपचार कक्ष** भी बनाए जाएंगे।

हमारे संकल्प

अनुसूचित जातियाँ, जनजातियाँ (SC/ST) और अन्य पिछड़े वर्ग (OBC)

6. **अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के उद्यमियों** के व्यवसाय वृद्धी के लिए **₹15 लाख तक ब्याजमुक्त ऋण** प्रदान किया जाएगा।
7. सरकार की सभी **आरक्षित नौकरियों** को संबंधित वर्ग के लोगों को ही प्रदान किया जाएगा और उन स्थानों को **लंबे समय तक रिक्त नहीं रहने दिया जाएगा।** इसके लिए प्रत्येक वर्ष जून और जनवरी में **नियमों के अनुसार वॉक-इन इंटरव्यू अभियान** चलाया जाएगा।
8. **आदिवासी कला, संस्कृति, जीवनशैली, प्रथाएँ-परंपराएँ, कौशल और पारंपरिक ज्ञान** का गहन अध्ययन करने के लिए समर्पित **"आदि क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी विश्वविद्यालय"** की स्थापना की जाएगी।
9. प्रत्येक जिले में **ओबीसी छात्रों के लिए संत गाडगे बाबा छात्रावास** बनाए जाएंगे।
10. **आदिवासी छात्रों के लिए नागपुर, नासिक, मुंबई, छत्रपति संभाजी नगर, पुणे और अमरावती में छात्रावासों** का निर्माण किया जाएगा।

अंत्योदय कल्याण

11. हम राज्य के सभी गरीबों को **खाद्य सुरक्षा और आवास** प्रदान करेंगे।
12. हम **आवश्यक वस्तुओं की कीमतें स्थिर करेंगे** ताकि पूरे महाराष्ट्र में परिवारों को बाजार के उतार-चढ़ाव से सुरक्षित किया जा सके।
13. **वीज बिलात ३०% कपात** करके सौर और अक्षय ऊर्जेवर ऊर्जा पर भर दिया जाएगा।
14. मांग के अनुसार विविध सामाजिक समूहों की **उन्नति और विकास के लिए आर्थिक विकास महामंडल** स्थापित किए जाएंगे।

15. **डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रम सफलता आवास योजना को पुनर्जीवित किया जाएगा,** जिसके तहत सफाई कर्मचारियों को **गृह स्वामित्व के अधिकार प्रदान** किए जाएंगे।
16. **अक्षय अन्न योजना** के अंतर्गत, **कम आय वर्ग के परिवारों को प्रति माह मुफ्त राशन** प्रदान किया जाएगा, जिसमें चावल, ज्वारी, मूंगफली का तेल, नमक, चीनी, हल्दी, सरसों, जीरा और लाल मिर्च पाउडर शामिल होंगे।
17. अगले पांच वर्षों में **36 लाख परिवारों को आवास** प्रदान किए जाएंगे।
18. ऐप आधारित कंपनियों के आपूर्ति क्षेत्र में असंगठित कामगारों के लिए **कल्याण मंडल स्थापित किया जाएगा।**
19. **तृतीयपक्ष समुदाय के कल्याण और सम्मान** के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

राहत और पुनर्वास

20. **2013-14 पुनर्वसन अधिनियम** प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा।
21. सभी प्रभावित व्यक्तियों की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए एक **समग्र पुनर्वसन नीति** विकसित करने तथा सहायता और पुनर्वसन प्रक्रियाओं के लिए **स्पष्ट मार्गदर्शक सिद्धांत** निर्धारित करने के लिए एक **समिति स्थापित** की जाएगी।
22. **पुनर्वसित बस्तियों को संबंधित स्थानीय स्वशासित संस्थाओं में शामिल किया जाएगा,** ताकि उन्हें स्वच्छ पानी, स्वच्छता, बिजली, स्वास्थ्य सेवाएँ, शिक्षा, और अन्य बुनियादी सुविधाओं जैसी आवश्यक सेवाएँ प्रदान की जा सके।

प्रशासन और व्यवस्था

हमारे संकल्प

कानून और व्यवस्था

1. **जबरन और धोखाधड़ी से धर्मांतरण के खिलाफ एक सख्त कानून बनाया जाएगा,** जिससे जबरदस्ती और भ्रामक धार्मिक धर्मांतरण से सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।
2. **अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को वापस भेजने** तथा राज्य में घुसपैठ पर रोक लगाने के लिए कठोर कानून और कार्यात्मक उपाय लागू किए जाएंगे।
3. **पुलिस विभाग में रिक्त पदों को भरने के लिए *'महा पुलिस भर्ती अभियान'*** चलाया जाएगा। पुलिस कर्मियों के लिए उत्तम आवास की व्यवस्था की जाएगी।

सुशासन

4. सरकार बनने के बाद, पहले 100 दिनों के भीतर, हम **'विज़न महाराष्ट्र 2029'** प्रस्तुत करेंगे।
5. **प्रशासन में 3 लाख रिक्त स्थानों को भरने** के लिए अगले **5 वर्षों का समयबद्ध कार्यक्रम** लागू किया जाएगा।
6. **शहरी नियोजन और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में 'Geospatial Technology'** का उपयोग करके नगर नियोजन को अधिक सटीकता से क्रियान्वित किया जाएगा।
7. महाराष्ट्र सरकार ने **सेवा गारंटी अधिनियम** लागू किया है ताकि आवेदकों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर सरकारी सेवाएँ प्राप्त हो सकें। इस कानून के अंतर्गत **महिलाओं, युवाओं, किसानों और वरिष्ठ नागरिकों से प्राप्त आवेदनों को प्राथमिकता दी जाएगी** और उनका तुरंत समाधान किया जाएगा।
8. स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को मजबूत करने के लिए, इन संस्थाओं में जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने हेतु **'उत्तमराव पाटिल प्रशिक्षण संस्थान'** की स्थापना की जाएगी।

जे का रंजले गांजले

आधारभूत संरचना

हमारे संकल्प

सड़क परिवहन सुविधा

1. हम महाराष्ट्र में कनेक्टिविटी और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए **सड़क, बंदरगाह, औद्योगिक अवसंरचनाओं और हवाई अड्डों** जैसे विभिन्न राज्य विभागों की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समेकित करते हुए **'महागतिशक्ति'** पहल शुरू करेंगे।
2. **मौजूदा बस स्टेशनों को विकसित** कर **बस पोर्ट्स** में परिवर्तित किया जाएगा। इसमें स्थानीय कलाओं को बढ़ावा देने के लिए रंगमंच, मराठी फिल्मों के लिए सिनेमा और स्थानीय कृषि उपज के लिए किसान बाज़ार जैसी सुविधाएं स्थापित किये जाएंगे।
3. हम मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और समृद्धि महामार्ग की तरह ही **5,000 किलोमीटर से अधिक लंबे आधुनिक एक्सप्रेसवे** बनाएंगे।

रेलवे परिवहन सुविधा

4. **वर्धा-यवतमाल-नांदेड़, अहमदनगर-परळी वैजनाथ, जालना-जळगाव, सोलापूर-तुळजापुर-धाराशिव, और पुणे-नाशिक** जैसे महत्वपूर्ण रेल मार्गों की पूर्णता के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे।
5. मुंबई को नागपुर, कोल्हापुर, नांदेड़ और लातूर से जोड़ने के लिए **अतिरिक्त वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों** की शुरुआत के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे।
6. केंद्र सरकार के सहयोग से **नमो भारत क्षेत्रीय तीव्र परिवहन प्रणाली (आरआरटीएस)** विकसित की जाएगी, जो **पुणे-जालना** और **पुणे-नासिक** शहरों को जोड़ेगी।

हवाई परिवहन सुविधा

7. महाराष्ट्र के प्रत्येक तालुका में **हेलिपैड का निर्माण** किया जाएगा, जिससे चिकित्सा आपातकाल के दौरान त्वरित सेवाएं प्रदान करना संभव होगा।

8. महाराष्ट्र के **16 जिलों में वाणिज्यिक हवाई सेवाओं का विस्तार** किया जाएगा। साथ ही, प्रत्येक जिले में एक रनवे स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा।

जलमार्ग परिवहन सुविधा

9. कोचि (केरल) की तर्ज पर **'वाटर मेट्रो'** शुरू की जाएगी, जो महाराष्ट्र के **तटीय शहरों और द्वीपों** को तीव्र जलमार्ग से जोड़ेगी।

10. अलीबाग, वर्सोवा, मालवन, अर्नाला और उत्तन में **मत्स्य बंदरगाहों का आधुनिकीकरण** किया जाएगा।

शहरी विकास

हमारे संकल्प

परिवहन और अवसंरचना

1. 2034 तक मुंबई (एमएमआर), पुणे, छत्रपति संभाजीनगर, नागपुर और नासिक जैसे शहरों में कुल **1,000 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क** विकसित किया जाएगा, जिससे सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा।

2. शहर में उपनगरीय रेल परिवहन, मेट्रो, मोनोरेल, शहरी बस सेवाओं, टैक्सियों, रिक्शा और फीडर रिक्शा के **निर्बाध उपयोग की सुविधा** के लिए **एक एकीकृत स्मार्ट कार्ड योजना लागू** की जाएगी।

स्वच्छता और कचरा प्रबंधन

3. **साल 2029 तक सभी सीवेज का शुद्धीकरण करने का लक्ष्य रखते हुए** वर्तमान प्रणाली की क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ आवश्यकता के अनुसार नई प्रणाली स्थापित की जाएगी। इसके साथ ही **महाराष्ट्र को खुले नालियों से मुक्त राज्य** बनाया जाएगा।

4. **महाराष्ट्र में समग्र कचरा प्रबंधन कार्यक्रम का कार्यान्वयन** किया जाएगा। जिसमें:

   a. पूरे राज्य में कचरा निपटान और पुनर्चक्रण प्रक्रिया की निगरानी और विनियमन के लिए **महाराष्ट्र कचरा प्रबंधन महामंडल** की स्थापना की जाएगी।

   b. **'रैग्स टू रोड्स'** योजना के माध्यम से सड़क निर्माण में 8% तक प्लास्टिक कचरे के उपयोग को अनिवार्य करके **'कचरे के पहाड़ों'** को खत्म किया जाएगा।

   c. ठोस कचरे को ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए राज्यभर में **वेस्ट-टू-एनर्जी पावर प्लांट्स की स्थापना** की जाएगी, जिसमें पहले चरण में **पांच महानगरों** में शुरुआत की जाएगी और धीरे-धीरे सभी बड़े शहरों में इसका विस्तार किया जाएगा।

हमारे संकल्प

5. महाराष्ट्र को सबसे स्वच्छ राज्य बनाने के लिए **'स्वच्छता विकास अभियान (SWACH)'** प्रारंभ किया जाएगा:
   a. **'महा स्वच्छता रैंकिंग'** शुरू की जाएगी और प्रत्येक शहर में **कचरा प्रसंस्करण केंद्र** स्थापित किए जाएंगे।
   b. **स्वच्छ बस स्टैंड, स्वच्छ सरकारी अस्पताल** जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।
   c. आवश्यकतानुसार विभिन्न स्थानों पर **सार्वजनिक शौचालय स्थापित किए** जाएंगे।

ग्रामीण विकास

हमारे संकल्प

डिजिटल कनेक्टिविटी और शिक्षा

1. हम **भारतनेट** के माध्यम से प्रत्येक गाँव में **100% ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी** की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

सतत विकास और पर्यावरण

2. **महाराष्ट्र सरोवर संवर्धन योजना** को राज्य स्तर पर शुरू किया जाएगा ताकि गांव स्तर पर जल निकायों का पुनरुद्धार किया जा सके, जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके और स्थानीय आजीविका को समर्थन दिया जा सके।

स्थानीय प्रशासन और समुदाय सशक्तिकरण

3. आगामी पांच वर्षों में **पीएम सूर्य-घर योजना** के अंतर्गत **प्रत्येक गांव में 25% घरों को सौर ऊर्जा** पहुंचाई जाएगी।
4. राज्य के कई स्थानों पर अंतिम संस्कार एक समस्या बनती जा रही है। **प्रत्येक मृतक को सम्मानजनक विदाई मिले,** यह सुनिश्चित करने के लिए **आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।**

संस्कृति, और पर्यटन

हमारे संकल्प

छत्रपति शिवाजी महाराज

1. महाराष्ट्र कई प्राचीन और ऐतिहासिक किलों का घर है, जो राज्य के गौरव के प्रतीक हैं और इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महाराष्ट्र के इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए **किला विकास प्राधिकरण (FDA)** स्थापित किया जाएगा।
2. किलों के संरक्षण के लिए काम करने वाले सरकारी मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित किया जाएगा, और **'दुर्ग सेवक'** और **'रक्षक'** जैसे उत्साही लोगों को उनके योगदान के लिए आधिकृत मान्यता दी जाएगी। **प्रत्येक किले के लिए समर्पित समितियां बनाई जाएंगी** ताकि उनके रखरखाव पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।
3. पुणे में महाराष्ट्र के विभिन्न साम्राज्यों के शौर्य और धरोहर की गाथा को प्रदर्शित करने वाला एक भव्य **'महाराष्ट्र इतिहास धरोहर पार्क एवं संग्रहालय'** स्थापित किया जाएगा।
   a. इस संग्रहालय में लेज़र शो, युद्ध पुनर्निर्माण, और वर्चुअल रियलिटी जैसी सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।
   b. इसके अतिरिक्त, पारंपरिक संगीत, नृत्य और कला रूपों सहित महाराष्ट्र की विरासत का उत्सव मनाने वाले सांस्कृतिक समारोह आयोजित किए जाएंगे।
4. **छत्रपति शिवाजी महाराज** की विरासत को संजोने के लिए, हम निम्नलिखित करेंगे:
   a. पन्हालगढ़ किले पर वीर **शिवा काशिद** का स्मारक।
   b. विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग में **सरखेल कान्होजी आंग्रे** का स्मारक और **मराठा नौसेना संग्रहालय।**
   c. **थोरले बाजीराव पेशवा** का जन्मस्थान डुबेरे, जिला नासिक में स्मारक-संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा।

हमारे संकल्प

मराठी भाषा

5. सभी भारतीय दूतावासों में और भारत के सभी राजभवनों में **स्थानीय मराठी लोगों की भागीदारी से महाराष्ट्र दिवस मनाया जाएगा** और **'फ्रेंड्स ऑफ़ महाराष्ट्र'** नेटवर्क स्थापित किया जाएगा।
6. **प्रत्येक जिले के मुख्यालय** पर **तीन दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव** शुरू किया जाएगा। इसमें संबंधित क्षेत्रों की मराठी भाषा, लावणी, भारुड़ और पोवाड़ा जैसी स्थानीय परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
7. हाल ही में **मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है।** इसके संदर्भ में, मराठी भाषा अनुसंधान संस्थाओं को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा और छात्रवृत्ति के माध्यम से मराठी भाषा के गहन अध्ययन को प्रोत्साहित किया जाएगा।

सांस्कृतिक धरोहर और संरक्षण

8. तुलजाभवानी मंदिर के विकास के लिए **पर्याप्त निधि सुनिश्चित की जाएगी** और इस मंदिर को प्रमुख हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों से जोड़कर **भक्तों को सुविधाजनक यात्रा सुविधाएं उपलब्ध** कराई जाएंगी।
9. **कोल्हापुर के ऐतिहासिक महालक्ष्मी मंदिर** में सुविधाओं के विकास और विस्तार के लिए **महालक्ष्मी मंदिर पुनर्विकास योजना लागू** की जाएगी।
10. **गोदावरी के घाटों का नवीनीकरण** और बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा ताकि **2027 में नासिक-त्र्यंबकेश्वर** में सिंहस्थ कुंभ मेला आयोजित किया जा सके।
11. त्र्यंबकेश्वर, पंचवटी, सप्तश्रृंगी, सोमेश्वर, नवश्या गणपति, मुक्तीधाम, शनि शिंगणापुर और शिर्डी जैसे तीर्थस्थलों को शामिल करते हुए **दिव्य दर्शन पर्यटन सर्किट** की शुरुआत की जाएगी।

12. **400 वर्ष से अधिक पुराने मंदिरों** का जीर्णोद्धार किया जाएगा।

13. संस्कृति और विरासत के संरक्षण में कॉर्पोरेट जगत की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, **सीएसआर निधि का एक निर्दिष्ट हिस्सा कॉर्पोरेट सांस्कृतिक उत्तरदायित्व (सीसीआर) के लिए आरक्षित किया जाएगा।**

14. स्थानीय विरासत स्थलों, ऐतिहासिक स्मारकों, कारीगरों, कलाकारों और कला रूपों को बढ़ावा देने के लिए राज्य में **स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के भीतर सांस्कृतिक समितियां स्थापित की जाएंगी** तथा आवश्यकतानुसार **प्रासंगिक कानूनों में संशोधन किया जाएगा।**

15. महाराष्ट्र के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का सम्मान करने के लिए हम:

    a. मंगलवेढा में **महात्मा बसवेश्वर** की स्मारक का निर्माण करेंगे।

    b. **संत चोखामेला** का जन्म स्थान, मेहुणा राजा, भंडारा में भव्य स्मारक का निर्माण करेंगे।

    c. पुणे के पिंपरी चिंचवड में **मोरया गोसावी** समाधी क्षेत्र का नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण किया जाएगा।

    d. पंढरपुर में **संत नामदेव महाराज स्मारक** की स्थापना करेंगे।

    e. सांगली के अरेवाडी में **बिरोबा मंदिर** का नवीनीकरण करेंगे।

16. **'श्री विठ्ठल सांस्कृतिक सर्किट'** की स्थापना की जाएगी, जिसमें **पंढरपुर, आळंदी, देहू, पैठण, त्र्यंबकेश्वर, सासवड, मुक्ताईनगर, आपेगाव और नेवासा** जैसे प्रमुख वारकरी तीर्थ स्थलों को जोड़ा जाएगा।

17. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्द **सारंगखेड़ा चेतक महोत्सव के ज़रिये** अश्वप्रदर्शन और महाराष्ट्र की पाक संस्कृति को बढ़ावा देगा।

18. **जलगांव जिले के मेहरून तालाब** के पुनरुद्धार और संवर्धन के लिए निधि उपलब्ध कराई जाएगी।

19. विभिन्न कला रूपों को बढ़ावा देने और कलाकारों को अपना कौशल दिखाने के लिए एक समर्पित मंच प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र में **ललित कला अकादमी** की एक शाखा स्थापित की जाएगी।

20. **नागपुर और चंद्रपुर में दीक्षाभूमि के पुनर्विकास** के लिए ₹300 करोड़ की परियोजना को शीघ्र पूरा किया जाएगा।

21. **महाराष्ट्र में सभी सरकारी और निजी संग्रहालयों** के विकास के लिए व्यापक योजना तैयार कर लागू की जाएगी।

22. विभिन्न तीर्थ स्थलों को पदयात्रा के माध्यम से आने वाले भक्तों को **सभी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।**

23. केन्द्र और राज्य सरकारों की विभिन्न विकास परियोजनाओं और विभिन्न सेवा पहलों के भ्रमण की सुविधा के लिए विशेष रूप से युवाओं के लिए **एक विकास पर्यटन योजना** लागू की जाएगी।

24. **गोंधल, दशावतारी खेले** जैसे पारंपरिक कला रूपों के साथ-साथ कारीगरों की पारंपरिक शिल्पकला का उचित दस्तावेजीकरण (पूर्व-लेखन) किया जाएगा तथा बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) हासिल किए जाएंगे, जिससे उनके मूल स्वरूप को मिलावट से बचाया जा सकेगा।

पर्यटन विकास

25. **स्थानीय युवाओं को पर्यटक मार्गदर्शक (गाइड) के रूप में प्रशिक्षित करने तथा प्रमाणित** करने के लिए एक योजना शुरू की जाएगी, जिससे ऐतिहासिक स्थलों, विशेषकर किलों पर गाइडों के लिए प्रमाणन प्राप्त करना अनिवार्य हो जाएगा।

26. पर्वतारोहण में व्यवस्थित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राज्य में **'तानाजी मालुसरे गिर्यारोहण संस्था'** की स्थापना की जाएगी।

27. कोंकण में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए **'कम टू कोंकण'** पहल शुरू की जाएगी। इस पहल से **तटीय पर्यटन, स्कूबा डाइविंग, बैकवाटर पर्यटन, इको-पर्यटन और खाद्य पर्यटन** सहित विभिन्न प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

28. **कास पठार को पर्यावरणीय रूप से स्थायी पर्यटन स्थल में विकसित** किया जाएगा, जिससे इको-पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और यहाँ की अद्वितीय जैव विविधता संरक्षित रहेगी। इसके अतिरिक्त पर्यावरण तथा स्थानीय निवासियों को लाभ होगा।

वन, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन

हमारे संकल्प

वन और वन्यजीव संरक्षण

1. कृषि एवं मानव बस्ती क्षेत्रों में बाघ, तेंदुआ, हाथी, नीलगाय, जंगली सूअर और बंदरों जैसे वन्यजीवों के कारण होने वाली **जान-माल की हानि को रोकने** तथा **मानव-पशु संघर्ष को कम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), ड्रोन और रेडियो कॉलर** जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रभावी उपयोग किया जाएगा।
2. **'एक पेड़ माँ के नाम'** पहल को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाएगा।
3. **जिला प्राकृतिक वास योजनाएं (District Habitat Plans)** पर्यावरणीय लक्ष्यों के अनुरूप विकसित की जाएंगी, जिनमें प्रत्येक जिले के **इकोसिस्टम की सुरक्षा** और कृषि, जल और भूमि संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
4. महाराष्ट्र के सभी समुद्र तटीय शहरों में **कांदळवन संरक्षण और पुनर्स्थापन कार्यक्रम** शुरू किए जाएंगे, जिसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी से कांदळवन संरक्षण और शहरी नियोजन का समावेश होगा।
5. **'सबसे बड़ा धन, जल और वन'** के नारे के अंतरगर्त स्थानीय समुदाय की भागीदारी से राज्य के हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सामुदायिक प्रबंधित वनों **(Community Managed Forests)** की स्थापना को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, **देवराई (पवित्र उपवन)** को उनकी अद्वितीय जैव विविधता और सांस्कृतिक महत्व के लिए संरक्षित किया जाएगा।
6. वन संवर्धन और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए **जिला और तालुका स्तर पर पुरस्कार** शुरू किए जाएंगे।

हमारे संकल्प

जल, भूमि और पारिस्थितिकी प्रबंधन

7. महाराष्ट्र की नदियों को स्वच्छ करने के लिए **अत्याधुनिक सफाई तकनीक** का उपयोग किया जाएगा, जिसमें **'रो-बोट' प्रणाली** का समावेश होगा।

8. **नदियों के तल में सिल्टेशन को रोकने** के लिए **रोकथाम के उपाय** किए जाएंगे, जिसमें **बांस और वेटिवर जैसी घनी घासों** का उपयोग किया जाएगा।

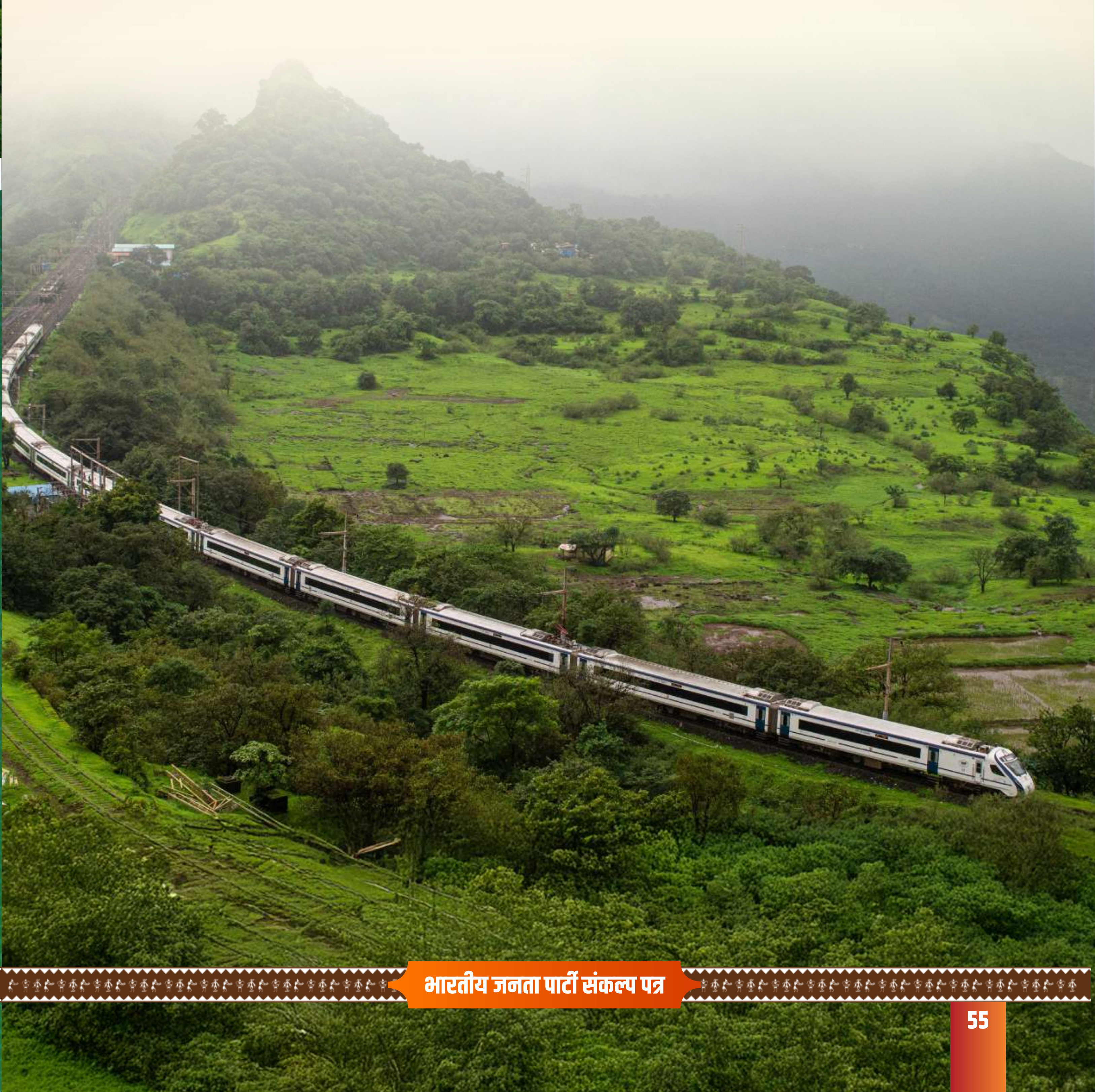

मुंबई महानगर क्षेत्र

हमारे संकल्प

1. मुंबई में समग्र शहरी विकास को सुनिश्चित करने के लिए **विकास नियंत्रण विनियम (DCR) 2034** का सख्ती से कार्यान्वयन किया जाएगा।

2. मुंबई के सभी म्हाडा (MHADA) आवासों का **पांच वर्ष में क्लस्टर के माध्यम से विकास** किया जाएगा।

3. हाल ही में घोषित नई आवास नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से **मुंबई को झुग्गी-झोपडी मुक्त बनाने के प्रयास** किए जाएंगे।

4. BEST बस बेड़े में **12,000 EV बसों का समावेश** कर, मुंबईवासियों के लिए पर्यावरण स्नेहि और किफायती यात्रा सुनिश्चित की जाएगी।

5. मुंबई महानगर क्षेत्र में आने वाली सभी नगर निगम सीमाओं में **खाली स्थान (सरकारी, अर्द्ध-सरकारी) अतिक्रमण मुक्त** रखने के लिए सक्षम तंत्र स्थापित किया जाएगा।

6. **डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रम साफल्य आवास योजना** को पुनः आरंभ किया जाएगा। मुंबई और सभी नगरीय स्थानीय स्वराज संस्थाओं में **सफाई कर्मियों को घर के मालिकाना हक** दिए जाएंगे।

7. मुंबई महानगर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर **फ्लाईओवर का निर्माण** किया गया है। उन फ्लाईओवरों के नीचे **टर्फ सुविधाओं का निर्माण** किया जाएगा, जिससे पहले अनुपयोगी खुले स्थानों का उपयोग खेल गतिविधियों के लिए किया जा सकेगा।

8. मुंबई को निकटवर्ती शहरों से जोड़ने के लिए **वंदे मेट्रो सेवा शुरू** की जाएगी। इससे यात्रा का समय महत्वपूर्ण रूप से कम होगा और मुंबई के आसपास के शहरों की मुंबई से निकटता बढ़ेगी।

9. कोचि (केरल) के तर्ज पर **'वॉटर मेट्रो'** शुरू की जाएगी। इसके माध्यम से तटीय शहरों और द्वीपों को **पर्यावरणस्नेही जलमार्गों** से जोड़ा जाएगा। इसके लिए **विद्युत नौकाओं (EV)** का उपयोग किया जाएगा। इससे मुंबई शहर की परिवहन व्यवस्था पर दबाव कम करने में सहायता मिलेगी।

10. महाराष्ट्र के शहरी क्षेत्रों में **बहुमंजिला स्वचालित पार्किंग व्यवस्था** स्थापित कर, पार्किंग और परिवहन समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

11. बारिश के मौसम में शहरों में पानी के जलभराव को रोकने के लिए मुंबई सहित सभी प्रमुख शहरों में **स्मार्ट ड्रेनेज सिस्टम** लागू किया जाएगा।

नोट्स

नोट्स

भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र

भाजपा मुख्यालय, सीडीओ बैरक 1, एलआईसी कार्यालय के सामने,
नरीमन प्वाइंट, मुंबई - 400021

भाजप-महायुती आहे, तर गती आहे

महाराष्ट्राची प्रगती आहे

कमल का बटन दबाएं भाजपा को जिताएं